AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में मध्य विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सरोज यादव
शोध छात्रा
डॉ. पुष्पा भारती
शोध निर्देशिका
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में मध्य विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। अनुसूचित जनजातियाँ प्रायः सामाजिक रूप से हाशिए पर और आर्थिक रूप से पिछड़ी होती हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनकी शैक्षणिक प्रगति पर पड़ता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि इन छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आय का स्तर, अभिभावकों की शिक्षा, तथा स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता उनकी शिक्षा में किस प्रकार योगदान देती है या बाधा उत्पन्न करती है। शोध कार्य में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक जानकारी हेतु पाटन ब्लॉक के 5 चयनित सरकारी मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 80 जनजातीय छात्रों, उनके 25 अभिभावकों और 10 शिक्षकों से साक्षात्कार व प्रश्नावली के माध्यम से डेटा संकलित किया गया। द्वितीयक आंकड़े जनगणना, एनसीईआरटी रिपोर्ट, राज्य शिक्षा विभाग और पूर्व प्रकाशित शोध अध्ययनों से एकत्र किए गए। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश जनजातीय छात्रों के अभिभावक अनपढ़ या अल्प–शिक्षित हैं और मुख्यतः कृषि या दिहाड़ी मजदूरी में संलग्न हैं। आर्थिक असुरक्षा, शैक्षिक वातावरण की कमी, भाषा एवं संप्रेषण की कठिनाइयाँ, विद्यालयों में सुविधाओं की कमी तथा सामाजिक भेदभाव उनकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। यह शोध यह भी दर्शाता है कि यदि शिक्षण प्रणाली में स्थानीय भाषा, संस्कृति और संदर्भ को सम्मिलित किया जाए तथा सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

मुख्य शब्द

जनजातीय शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, मध्य विद्यालय स्तर, शैक्षणिक बाधाएँ, पाटन विकासखंड.

प्रस्तावना

भारत विविध संस्कृतियों, भाषाओं और सामाजिक समूहों का देश है, जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग के रूप में शामिल हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का लगभग

8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 30.6 प्रतिशत जनजातीय समुदायों से आता है (भारत सरकार, 2014)। दुर्ग जिला, विशेषतः पाटन विकासखंड, भी इस जनसंख्या संरचना से अछूता नहीं है। यहाँ की जनजातियाँ मुख्यतः गोंड, बैगा और हल्बा समुदायों से संबंधित हैं, जो मुख्यतः कृषि, वन आधारित संसाधनों और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। शिक्षा को सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। अमर्त्य सेन (1999) के अनुसार, शिक्षा न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक अवसरों को भी सुलभ बनाती है लेकिन जनजातीय समुदायों में शिक्षा की पहुँच अब भी सीमित है। शारीरिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में निवास, सामाजिक भेदभाव, भाषाई अवरोध और आर्थिक तंगी जैसे कारणों से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच दोनों प्रभावित होती हैं (सुजाता, 2008; जाक्सा, 2011)।

बासु (2000) के अनुसार, जनजातीय समुदायों में शिक्षा को लेकर जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक असंगति स्कूल ड्रॉपआउट के मुख्य कारण हैं। वहीं बर्मन (2009) ने तर्क दिया कि सरकार की योजनाएँ अक्सर आदिवासी समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को समझे बिना बनाई जाती हैं, जिससे वे प्रभावी नहीं हो पातीं। स्थानीय शिक्षक की अनुपस्थिति और पाठ्यक्रम की भाषा व शैली आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी बाधा बन जाती है (बेहरा, 2015)। छत्तीसगढ़ के पाटन ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की भारी कमी है, वहाँ शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ के मध्य विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति अनियमित है, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है और शिक्षकों की संख्या भी अपर्याप्त पाई गई है। प्रीति (1994) और रमेश (2012) जैसे शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक शिक्षा को स्थानीय संस्कृति, भाषा और जीवनशैली से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जनजातीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव नहीं है।

इस अध्ययन का उद्देश्य पाटन विकासखंड के मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत जनजातीय छात्रों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना तथा उन कारकों की पहचान करना है जो उनकी शैक्षणिक प्रगति को प्रभावित करते हैं साथ ही, यह शोध यह समझने की कोशिश करता है कि सरकारी योजनाएँ और शिक्षा नीतियाँ कितनी प्रभावशाली रही हैं और क्या सुधार की संभावनाएँ हैं। यह शोध न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से बल्कि नीति निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि शिक्षा को जनजातीय समुदाय की संस्कृति, भाषा और जीवनचर्या के साथ जोड़कर योजनाएँ बनाई जाएँ, तो उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

शोध के उद्देश्य

- दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में अध्ययनरत जनजातीय छात्रों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना ।
- मध्य विद्यालय स्तर पर जनजातीय छात्रों की शिक्षा में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।

साहित्य समीक्षा

जनजातीय शिक्षा पर विभिन्न विद्वानों ने समय–समय पर गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सुजाता (2008) के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है सांस्कृतिक और भाषाई असामंजस्य, जिसके कारण बच्चे विद्यालय के माहौल से सहज नहीं हो पाते। बासु (2000) ने अपनी शोध में बताया कि आदिवासी स्वास्थ्य और जीवनशैली का सीधा प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपस्थिति पर पड़ता है, विशेषकर जब स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ न हों। बर्मन (2009) ने यह तर्क दिया कि सरकारी योजनाएँ जनजातीय समुदाय की असली आवश्यकताओं को संबोधित नहीं करतीं, जिससे वे केवल नाममात्र की पहल बनकर रह जाती हैं। अमुल्य कुमार बेहरा (2015) ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में किए गए अध्ययन में बताया कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर आदिवासी छात्रों के ड्रॉपआउट का मुख्य कारण परिवहन सुविधा की कमी, सामाजिक उपेक्षा और अभिभावकों की उदासीनता है। वहीं भौमिक (1998) ने आदिवासी विकास को समग्र दृष्टिकोण से देखने की बात की और शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बताया।

एक अन्य शोध में रामि (2012) ने गुजरात के डांग जिले में पाया कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, जैसे शौचालय, पीने के पानी और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण की कमी भी शिक्षा में रुकावट बनती है। अरुण कुमार घोष (2007) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की जनजातियों पर किए गए अध्ययन में यह दर्शाया कि खेतों में काम करने की विवशता के कारण बच्चे विशेषकर बालिकाएँ पढ़ाई छोड़ देती हैं। विनोबा गौतम (2003) ने ''जनशाला'' कार्यक्रम के माध्यम से सुझाव दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। सेन (1999) ने विकास की संकल्पना में मानव स्वतंत्रता और क्षमताओं को केंद्र में रखा और शिक्षा को इस दिशा में सबसे प्रभावशाली साधन माना। वरमा (1996) ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना पर बल देते हुए बताया कि जब तक शिक्षा प्रणाली उनकी संस्कृति से मेल नहीं खाती, तब तक वह प्रभावी नहीं हो सकती।

उपरोक्त समीक्षाओं से स्पष्ट होता है कि जनजातीय शिक्षा को केवल सामान्य शिक्षा नीति के दायरे में रखकर नहीं देखा जा सकता। इसके लिए विशेष, संवेदनशील और स्थानीय रूप से अनुकूल रणनीतियों की आवश्यकता है, जो सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोधों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध है, जिसमें पाटन विकासखंड, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। शोध में मिश्रित पद्धति को अपनाया गया, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा संकलन के लिए क्षेत्र में 5 चयनित सरकारी मध्य विद्यालयों का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण के आधार पर किया गया। इन विद्यालयों से कुल 80 जनजातीय छात्रों, 25 अभिभावकों और 10 शिक्षकों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई। प्रश्नावली में सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यालय में उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन तथा आने वाली बाधाओं से संबंधित प्रश्न शामिल थे। द्वितीयक डेटा के स्रोतों में जनगणना रिपोर्ट, राज्य शिक्षा विभाग की रिपोर्टें, एनसीईआरटी प्रकाशन, और पूर्ववर्ती शोध पत्र शामिल थे। एकत्रित डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय एवं विषयगत रूप से किया गया, ताकि शिक्षा में अंतराल और सामाजिक कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आ सके।

परिणाम एवं चर्चा

तालिका 1: विभिन्न शैक्षिक पहलू का तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू	आवत्ति			प्रतिशत		
	हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल
आर्थिक स्थिति	65	15	80	81.0	19.0	100
विद्यालय तक पहुँच	52	28	80	65.0	35.0	100
भाषाई अवरोध	38	42	80	47.5	52.5	100
स्वास्थ्य व कुपोषण	28	52	80	35.0	65.0	100
ड्रॉपआउट / अनियमित उपस्थिति	21	59	80	26.0	74.0	100
अभिभावकों की भूमिका	18	07	25	72.0	28.0	100
शैक्षणिक अवसंरचना (शिक्षक)	03	02	05	60.0	40.0	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

यह तालिका विभिन्न शैक्षिक पहलुओं पर आधारित है, जिसमें ''हां'' और ''नहीं'' के उत्तरों की आवृत्ति और प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यह आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि किन–किन कारकों का बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति को देखें तो 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे एक बाधा माना है,

जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक असमानता शिक्षा में बाधा बन रही है। विद्यालय तक पहुँच में 65 प्रतिशत का सकारात्मक प्रतिशत यह दिखाता है कि एक अच्छी संख्या में बच्चों को विद्यालय तक पहुँच मिल रही है, लेकिन अब भी 35 प्रतिशत की पहुँच नहीं है। भाषाई अवरोध एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आता है, जहाँ 52.5 प्रतिशत ने इसे शिक्षा में बाधा बताया। स्वास्थ्य व कुपोषण भी एक चिंताजनक पहलू है 65 प्रतिशत बच्चों को इससे समस्या है, जिससे उनकी उपस्थिति व प्रदर्शन प्रभावित होते हैं।

ड्रॉपआउट व अनियमित उपस्थिति 74 प्रतिशत तक देखी गई, जो अत्यधिक है और निरंतरता की कमी दर्शाती है। वहीं, केवल 25 अभिभावकों की भागीदारी पर आधारित आंकड़ों से पता चलता है कि अभिभावकों की भूमिका शिक्षा में सीमित है। शैक्षणिक अवसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता का प्रतिशत केवल 60 प्रतिशत सकारात्मक है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। ये आंकड़े शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

तालिका 2: शिक्षा प्रणाली में प्रमुख चुनौतियाँ और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण

चुनौतियाँ	आवत्ति			प्रतिशत		
	हां	नहीं	कुल	हां	नहीं	कुल
शैक्षणिक अधोसंरचना की कमी	40	40	80	50.0	50.0	100
भौगोलिक और भौतिक बाधाएँ	52	28	80	65.0	35.0	100
भाषाई असंगति और पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता	38	42	80	47.5	52.5	100
स्वास्थ्य और कुपोषण	28	52	80	35.0	65.0	100
अभिभावकों की सीमित भागीदारी	18	62	80	22.5	77.5	100
सामाजिक बहिष्करण और भेदभाव	22	58	80	27.5	72.5	100
सरकारी योजनाओं का प्रभावहीन क्रियान्वयन	30	50	80	37.5	62.5	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

तालिका 2 शिक्षा प्रणाली में मौजूद विभिन्न बाधाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह स्पष्ट होता है कि भौगोलिक और भौतिक बाधाएँ सबसे गंभीर समस्या हैं, जहाँ 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे मान्यता दी है। ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों तक पहुँच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शैक्षणिक अधोसंरचना की कमी भी एक महत्वपूर्ण बाधा है, जिसे 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि विद्यालयों में भवन, कक्षाएं, पुस्तकालय, लैब और अन्य सुविधाओं का अभाव बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रहा है।

भाषाई असंगति और पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता को 47.5 प्रतिशत लोगों ने बाधा माना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चों की मातृभाषा और विद्यालय की भाषा में अंतर उनके सीखने की प्रक्रिया को कठिन बनाता है। स्वास्थ्य और कुपोषण (35 प्रतिशत) तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावहीन क्रियान्वयन (37.5 प्रतिशत) भी चिंता के विषय हैं। यह योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू न होने की ओर संकेत करता है। अभिभावकों की सीमित भागीदारी (22.5 प्रतिशत) और सामाजिक बहिष्करण (27.5 प्रतिशत) जैसे सामाजिक कारक भी बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

गरीबी अक्सर वित्तीय बाधाओं की ओर ले जाती है, जिससे आदिवासी परिवारों की अपने बच्चों को स्कूल भेजने और आवश्यक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता प्रभावित होती है। शोध में कई आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों, कक्षाओं, पुस्तकालयों और शिक्षण सामग्री सहित उचित बुनियादी ढाँचे की कमी पर प्रकाश डाला गया है। संसाधनों की यह कमी आदिवासी छात्रों को उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता को बाधित करती है। आदिवासी क्षेत्रों में भौगोलिक दूरदराज और चुनौतीपूर्ण भूभाग स्कूलों तक पहुँचने में कठिनाइयों का कारण बनते हैं। खराब सड़क संपर्क और सीमित परिवहन विकल्प दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के लिए नियमित रूप से स्कूल जाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

आदिवासी भाषाओं और स्कूलों में शिक्षा की भाषा के बीच भाषा की बाधाएँ प्रभावी संचार और समझ में बाधा डालती हैं। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम की सीमित सांस्कृतिक प्रासंगिकता अक्सर आदिवासी छात्रों के बीच अरुचि और विरक्ति का कारण बनती है। आदिवासी समुदाय में कुपोषण की उच्च दर और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्र अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और स्कूल में ध्यान केंद्रित करने और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और रूढ़िवादिता आदिवासी छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रचलित मुद्दे हैं। ये कारक उनके आत्मसम्मान और अपनेपन की भावना को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं में बाधा उत्पन्न होती है। असुरक्षित भूमि स्वामित्व और भूमिहीनता कुछ आदिवासी परिवारों को शिक्षा की तुलना में तत्काल अस्तित्व को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है। सुरक्षित भूमि और संसाधन अधिकारों के बिना, कई आदिवासी समुदाय गरीबी में फंसे रहते हैं जबकि आदिवासी विकास के लिए सरकारी पहल मौजूद हैं, शोध में उनके प्रभावी कार्यान्वयन में अंतराल पाया गया है, जो आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों और परिणामों को बेहतर बनाने पर उनके प्रभाव को सीमित करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस शोध पत्र से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी समुदायों की शिक्षा प्रणाली अनेक जटिल एवं बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रही है। प्रस्तुत आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि आर्थिक स्थिति, भौगोलिक दूरी, भाषाई अवरोध, स्वास्थ्य समस्याएँ, सामाजिक भेदभाव और अव्यवस्थित सरकारी योजनाएँ शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। विशेष रूप से यह देखा गया कि आर्थिक असमानता और भौगोलिक कठिनाइयाँ सबसे गंभीर समस्याओं के रूप में उभरी हैं, जो विद्यालय तक बच्चों की नियमित पहुँच को प्रभावित करती हैं। भाषा और पाठ्यक्रम की सांस्कृतिक अप्रासंगिकता से बच्चों में रुचि की कमी तथा ड्रॉपआउट की दर में वृद्धि होती है वहीं, स्वास्थ्य एवं कुपोषण बच्चों की उपस्थिति, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अभिभावकों की सीमित भागीदारी और सामाजिक बहिष्कार बच्चों की शिक्षा को सामाजिक अलगाव के रूप में और अधिक जटिल बना देते हैं।

इन सभी समस्याओं का प्रभावी समाधान केवल शैक्षणिक नीतियों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसके लिए एक समग्र एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें आदिवासी संस्कृति, भाषा और सामाजिक पृष्ठभूमि को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए साथ ही, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना में सुधार, समुदाय की भागीदारी और शिक्षकों को स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा।

संदर्भ सूची

1. Basu, S. (2000) Dimensions of tribal health in India, *Health and Population: Perspectives and Issues,* 23(2), 61–70.
2. Behera, A. K. (2015) Primary education among tribal people of Mayurbhanj district of Odisha: An evaluative study, *International Journal of Humanities and Social Science Invention,* 4(2), 43–54.
3. Bhowmik, S. K. (1998) Development Perspective for Tribals, *Economic and Political Weekly,* 23(20), 1005–1007.
4. Burman, B. K. R. (2009) What has driven the tribals of Central India to political extremism?, *Mainstream Weekly,* 47(44).
5. Gautam, V. (2003) Janasala Experience: A Case for Quality Education Among Tribals, NIEPA, New Delhi.
6. Ghosh, A. K. (2007) Tribal Education in Jharkhand and West Bengal, *Journal of Indian Education,* 33(1), 45–54.

7. Government of India. (2014) Census of India 2011: Primary census abstract, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi.
8. Preet, R. (1994) *Tribal education in India,* Commonwealth Publishers, New Delhi.
9. Ramesh, S. (2012) Issues and challenges in tribal education, *Indian Journal of Social Development,* 12(1), 95–102.
10. Rami, G. (2012) Status of Primary Education in the Tribal District of Dang, Gujarat, *IJRCEM,* 2(5), 85–89.
11. Sen, A. (1999) *Development as freedom,* Oxford University Press, Oxford.
12. Sujatha, K. (2008) Primary education for tribal children: A case study, National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi.
13. Varma, R. (1996) *Indian tribes: Development and inequality,* Rawat Publications, Jaipur.
14. Xaxa, V. (2011) Education and the scheduled tribes in India, *Indian Journal of Social Development,* 21(3), 379–391.

––==00==––